

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 180/2017/223 आर टी ए

1. बीकरसिंह पुत्र भोलासिंह जाति जटसिख निवासी धौलीपाल हाल आबाद प्योरी तहसील गिदडबाहा जिला मुक्तसर पंजाब।

—अपीलांत

बनाम

1. घुकरसिंह पुत्र भोलासिंह जाति जटसिख निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. भोलासिंह पुत्र भागसिंह जाति जटसिख निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

— रेस्पोडेंटस

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 13.04.2015 व डिक्री दिनांक 20.04.2015 न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़ प्र0 सं0 122/2014 अनवानी घुकरसिंह बनाम भोलासिंह उपस्थित :-

- श्री सोमप्रकाश शर्मा अधिवक्ता अपीलांत
श्री राजेशदीप राय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
श्री गुरमोहनसिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3

निर्णय

दिनांक:-13.08.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश किया कि रेस्पो0 के पूर्वजो की भूमि गांव प्योरी तहसील गिदडबाहा मे थी जिसकी आय के उपार्जन से रेस्पो0 सं. 2 भोलासिंह ने अन्य भूमि के अलावा चक 10 डीएलपी के खाता सं. 17/11 मे 0.631 है0 व खाता सं. 79/53 मे 0.455 है0 तथा चक 12 एमएमके खाता सं. 13/16 की 2.746 है0 भूमि खरीद की। जिससे उपरोक्त वर्णित भूमि पैतृक सम्पति है। जिसमे रेस्पो0 सं. 1 का जन्म से हक व अधिकार निहित है। रेस्पो0 ने अर्सा पूर्व इस आराजी का गांव प्योरी की भूमि को शामिल करते हुए घरुबंटवारा कर लिया था। मुताबिक बंटवारा गांव प्योरी की भूमि रेस्पो0 सं. 2 भोलासिंह को प्राप्त हुई व चक 10 डीएलपी के खाता सं. 17/11 मे वर्णित 0.631 है0 भूमि मे से रेस्पो0 सं. 1 को व शेष बची भूमि रेस्पो0 सं. 2 को प्राप्त हुई व चक 12 एमएमके के खाता सं. 13/16 की 2.746 है0 भूमि मे से 2.024 है0 भूमि रेस्पो0 सं. 1 को व शेष बची भूमि रेस्पो0 सं. 2 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद पत्र डिक्री कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से

अपीलांट प्रभावित एवं पीडित पक्षकार है। अपीलांट रेस्पो0 सं. 2 का सगा पुत्र है एवं रेस्पो0 सं. 1 का सगा भाई है। रेस्पो0 ने आपस में संधि कर कपटपूर्वक तरीके से अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये वाद डिक्री करवा लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 2 भोलासिंह के रेस्पो0 सं. 1 घुकरसिंह व अपीलांट हकीकी पुत्र है जिससे रेस्पो0 सं. 2 के नाम की उपरोक्त वर्णित सम्पति कुल 2.746 है0 में अपीलांट का रेस्पो0 सं. 1 व 2 के साथ बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा बनता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र में रेस्पो0 द्वारा जानबूझकर अपीलांट पक्षकार न बनाकर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित करवाई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्ण आरबीजे2015 पेज 474 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि बिना पक्षकार बनाये न्यायालय द्वारा पारित आदेश असंगत है व इसी क्रम में आरबीजे 2017 पेज 189 में भी स्पष्ट किया है कि रिकार्ड में दोनों पक्षों को सुनकर ही घोषणा की जा सकती है। इसलिये आवश्यक पक्षकारान को पक्षकार बनाकर पुनः निर्णय करने बाबत पत्रावली प्रेषित की गई। हस्तगत प्रकरण में भी परिस्थितियां प्रस्तुत न्यायिक नजीरो के अनुकूल हैं। इसके अलावा स्वीकारोक्त रूप से प्रश्नगत भूमि जद्दी जायदाद है व कानूनन जद्दी जायदाद में पिता के साथ पुत्रों व पुत्रों का बहिस्सा बराबर का हक होता है, प्रश्नगत सम्पति में अपीलांट का कानूनन रेस्पो0 सं. 2 के साथ जन्म से हक व अधिकार था व है। रेस्पो0 सं. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रस्तुत किया है व दस्तावेज लिखित दिनांक 10.05.16 रिकार्ड पर लेने का अनुतोष चाहा है। इस संबंध में निवेदन है कि यह दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के बाद का दस्तावेज है जो हस्तगत प्रकरण के निस्तारण में किसी भी प्रकार से सुसंगत दस्तावेज नहीं है तथा ना ही यह दस्तावेज की श्रेणी में आता है। यह दस्तावेज अपीलांट की भूमि में रेस्पो0 सं. 1 द्वारा दखलअंदाजी देने के संबंध में पुलिस थाना हनुमानगढ़ में प्रस्तुत किया गया था जिसका मौतविरान द्वारा राजीनामा करवाया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के संबंध में इस दस्तावेज में कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह दस्तावेज सारहीन होने से रिकार्ड पर नहीं लिया जा

सकता। अधिवक्ता द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरुद्ध पेश की है जो पारित निर्णय व डिक्री के 60 दिवस के भीतर प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी लेकिन पूर्ववर्ती अनुसार अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया जिस कारण अपीलांट को उक्त निर्णय व डिक्री का ज्ञान नहीं था व ज्ञान होते ही अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत कर दी गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयानुसार बिना पक्षकार बनाये व अवैध निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने के लिए कोई मियाद अवधि निश्चित नहीं है व ऐसे अवैध निर्णय को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त की जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपने जवाब लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट का यह कथन कतई गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने आपस में दुर्भिसंधि कर अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना निर्णय पारित किया हो, वस्तुतः अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 व 2 का समस्त भूमि का घरू विभाजन हुआ जिसकी लिखित दिनांक 10.05.2016 को अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 व 2 के मध्य लिखापट्टी की गई, उक्त घरूबंटवारा मौका पर लागू भी हो गया और घरूबंटवारा के तहत ही अपीलांट व रेस्पो0 के नाम भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में वर्णित भूमि रेस्पो0 सं. 2 के नाम थी तथा घरू विभाजन में रेस्पो0 सं. 1 को प्राप्त हुई थी। इस कारण अपीलांट को उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं थी। अपीलांट घरूबंटवारा दिनांक 10.05.2016 से इन्कार नहीं किया है। उक्त घरूबंटवारा के मताबिक ही भूमि अपीलांट के नाम दर्ज हुई थी। जिसके नामान्तरण की प्रमाणित प्रतिलिपि रेस्पो0 ने प्रस्तुत की है। अपीलांट घरूबंटवारा दिनांक 10.05.2016 के विरुद्ध कथन करने से विबंधित है। अपीलांट को निर्णय व डिक्री का शुरू से ही ज्ञान रहा है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से किसी प्रकार से प्रभावित नहीं है। अपीलांट का यह कथन कतई मिथ्या है कि बंटवारानामा अपील हाजा से सुसंगत दस्तावेज न हो। अपीलांट ने इस दस्तावेज के खण्डन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन में आरबीजे 2009 पेज 16 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

5. अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा आरबीजे (22) 2015 पेज482 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए मुख्य रूप से तर्क दिया कि बिना पक्षकार बनाये निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने के लिए कोई मियाद अवधि निश्चित नहीं है व ऐसे निर्णय को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय आरबीजे 2015 पेज 474 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि बिना पक्षकार बनाये न्यायालय द्वारा पारित आदेश असंगत है व इसी क्रम में आरबीजे 2017 पेज 189 में भी स्पष्ट किया है कि रिकार्ड में दोनों पक्षों को सुनकर ही घोषणा की जा सकती है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को ना तो पक्षकार बनाया गया और ना ही कोई सुनवाई का अवसर दिया गया।
6. अपीलांट द्वारा यह उक्त अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट पक्षकार नहीं था इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मददेनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलांट अंदर मियाद शुमार की जाती है। अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ दस्तावेज आंशिक सत्यप्रति राजीनामा निर्णय में सहायक सिद्ध होने के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किये जाकर संलग्न दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाता है।
7. बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष है कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पो0 द्वारा अपने पिता भोलासिंह के विरुद्ध दावा प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि को जद्दी जायदाद/पैतृक होने कथन करते हुए घोषणा का अनुतोष चाहा गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा डिक्री कर दिया जबकि रेस्पो0 सं. 1 के एक भाई अपीलांट यानि रेस्पो0 सं. 2 भोलासिंह के दो पुत्र हैं जबकि दावा केवल मात्र रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अपने पिता भोलासिंह को पक्षकार बनाते हुए पेश किया गया और अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये जद्दी जायदाद भूमि के संबंध में घोषणा का दावा डिक्री करवाया गया है। वादग्रस्त भूमि सांझा खाता अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 व 2 के नाम दर्ज थी। जिसमें रेस्पो0 सं. 1 व 2 के साथ अपीलांट भी आवश्यक पक्षकार था क्योंकि वादग्रस्त भूमि के संबंध में घरबंदतारा के अनुसार घोषणा का

अनुतोष चाहा गया था। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2015 पेज 474, आरबीजे 2017 पेज 189 के अनुसार रिकार्ड में दोनों पक्षों को सुनकर ही घोषणा की जा सकती है तथा बिना पक्षकार बनाये न्यायालय द्वारा पारित आदेश असंगत है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई जिसकी पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना उचित नहीं होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.04.2015 व डिक्री दिनांक 20.04.2015 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट को बतौर पक्षकार संयोजित करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति से सहित लौटाई जावें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.09.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official